

सम्पादकीय

जनगणना का बहुप्रतीक्षित फैसला

पूरे चार वर्ष के विलम्ब से ही सही, अंततः केन्द्र सरकार ने अगले साल यानी 2025 में देश में जनगणना कराने का फैसला लिया है। यह काम कम से कम एक वर्ष तक चलेगा और आंकड़ों के परीक्षण, वर्गीकरण एवं अंतिम जनसांख्यिकीय के प्रकाशन में एक और साल लग जाने का अनुमान है। यानी 2026 तक ही यह काम पूरा हो सकेगा। वैसे लक्ष्य यहीं होगा कि 2028 तक होने वाले परिसीमन तक यह बड़ा काम पूर्ण हो जाये। सामान्य तौर पर जनगणना का उद्देश्य सामाजिक विकास के उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है परन्तु लगता है कि केन्द्र सरकार ने 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव को सामने रखकर यह फैसला लिया है। 2025 में जनगणना कराने के कारण अगली 2035 में होगी भारत में 1872 में पहली जनगणना हुई थी जिसे लॉर्ड मेयो की देखरेख में कराया गया था। हालांकि इस गणना का परीक्षण आदि हेनरी वाल्टर के अधीन हुआ था इसलिये उन्हें ही भारतीय जनगणना का जनक मान जाता है। बिटिश उपनिवेश होने के कारण भारत में भी दशक के शुरूआत में जनगणना कराने की व्यवस्था हुई। अब लगभग पूरी दुनिया में जनगणना का समय यहीं होता है। इस परम्परा का निर्वाह करते हुए स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई जो हर साल बदलती जारी रही। इसके कारण भारत को विश्व भर के देशों द्वारा होने वाली जनगणना के साथ तालिकें करने में सुविधा होती है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। आर्थिक जनगणना का प्रारम्भ 1976-77 में हुआ था। इसका उद्देश्य देश की आर्थिक संरचना का विश्लेषण करने के लिये होता है। इसमें देश की आर्थिक संस्थाओं के आंकड़े एकत्र किये जाते हैं जो केन्द्र या राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं बनाने में सहायक होते हैं। सम्भूत भारत में 15 बार बिला नागा होने वाली जनगणना को आजावद हिन्दुस्तान में पहली बार 2021 में कोविड-19 के कारण टाला गया था। हालांकि परिस्थितियां 2022 तक ऐसी हो चुकी थीं कि जनगणना कराई जा सके लेकिन देश की प्रशासकीय अराजकता के लिये यह मुफीद था कि जनगणना न हो। कोरोना के कारण लोगों के मरने वालों की संख्या, भूख से प्रभावित लोग, बेरोजगार आदि की संख्या आज भारत सरकार के पास नहीं है। रोजगार पर हुई एक बहस में सरकार ने संसद तक बताया कि उसके पास इसके आंकड़े नहीं हैं। जितने भी योजनाएं चल रही हैं, उनमें हितग्राहियों या जरूरतमंदों सम्बन्धी तमाम आंकड़े संदेहास्पद हैं। इसके कारण कोई भी कार्यक्रम वैज्ञानिक आधार पर क्रियान्वित नहीं हो रहे हैं। केन्द्र सरकार ने 2019-20 में आर्थिक जनगणना तो कराई पर उसका आधार 2011 के ही पुराने आंकड़े थे बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के दो निर्णयों का असर इन आंकड़ों में सच्चाई के साथ परिलक्षित नहीं हुआ है- नोटबन्दी एवं जीएसटी जिन्होंने भारत के आर्थिक परिवृश्य पर बहुत विपरीत प्रभावात्मक छोड़ा था, परन्तु लोगों की वास्तविक वित्तीय स्थिति को कभी उजागर नहीं किया गया। स्पष्टः ऐसा इन दो कदमों को गलत साबित होने से बचाने के किया गया। संसद में भी पहले-पहल इन दोनों निर्णयों को सकारात्मक पहल तो बताया गया पर बाद में उन पर चर्चा बन्द हो गयी।

वोकल फॉर लोकल उत्पादों संग मनाएं दिवाली !

सुनील कुमा

दापावला राशन का त्योहार हो यह उमंग-उत्साह, उल्लास, खुशियों व आपसी सौहार्द, मेल-मिलाप का त्योहार है। देखा जाए तो यह त्योहार पर्यावरण की रक्षा करने, पर्यावरण को शुद्ध, सुंदर व संतुलित रखने का भी त्योहार है। यह हमारे देश की सांस्कृतिक परंपराओं को जिंदा रखने, हमारे संस्कृति-संस्कार, बुराई पर अच्छाई की जीत का पावन व पवित्र त्योहार है, लेकिन पिछले कुछ सालों से दीपावली पर पटाखों से होने वाला वायु व ध्वनि प्रदूषण जहां एक ओर हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहा है वहीं दूसरी ओर इसके मानव व जीवों के स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं। ऐसे में हम सभी को यह जरूरत है कि हम दीपावली को ग्रीन पटाखों, रंगोली, मांडपा, वोकल फॉर लोकल उत्पादों का प्रयोग कर मनाएं। हम दिवाली पर अपनों को गिफ्ट दें और गिफ्ट्स का आदान-प्रदान कर दिवाली मनाएं। आज हमारे यहां दिवाली पर चाइनीज लाइट्स, झालारों की भरमार है और वे खूब बिक रही हैं। आज फैंसी लाइट्स, सजावट के विभिन्न सामानों से हमारे बाजार पटेल पड़े हैं और बाजार में इनकी भरमार है। देसी सामान/देसी उत्पादों की ओर हालांकि लोग धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं लेकिन विशेषकर चीन में बने उत्पादों में आज भी हमारा विश्वास कुछ ज्यादा ही है, इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी कहीं न कहीं बद्दा लग रहा है। आज चायनीस खिलाने, पटाखे हर गली हर मोहल्ले बिकते देखें जा सकते हैं, क्यों कि ये बहुत सस्ते हैं। हमें यह चाहिए कि हम मिट्टी के दीपकों का इस दीपावली ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें और विदेशी उत्पादों का बिहिष्कार करें। बाजार से हम मिट्टी के दीयों के अलावा देसी सामान जैसे कि तोरन, बंदनवार, हैंगिंग व पानी वाले दीये, मेटल के धीरे खरीदें। बाजारी मिलावटी मिठाईयों से बचें और घर पर ही मिठाईयां तैयार करें अथवा किसी अच्छे ब्रांड या किसी अच्छी दुकान से बढ़िया मिठाईया खरीदें। एक अनुमान के अनुसार दिवाली पर अपनों को गिफ्ट देने में करीबन 1.85 किए जान का अनुमान है जो एक बहुत बड़ी धनराशि है। आज पारंपरिक मिठाईयों के स्थान पर महंगे एंड्रेड्यूड फोन, कपड़े, इलैक्ट्रोनिक आइटम्स, गहने और अन्य उपहारों पर खर्च करने की होड़ बढ़ी है। हम सादगी, संयम को भूल रहे हैं और आधुनिकता के रंग में रंगकर त्योहारों के अर्थ को एक प्रकार से धूमिल कर रहे हैं। आज त्योहार पर दिखावा व बनावटीपन अधिक है। दिवाली पर पटाखों से होने वाला वायु प्रदूषण जहां एक ओर हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहा है वहीं दूसरी ओर इसके मानव व जीवों के स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं। ऐसे में हम सभी को यह जरूरत है कि हम दीपावली को ग्रीन पटाखों, रंगोली, मांडपा, वोकल फॉर लोकल उत्पादों का प्रयोग कर मनाएं। हम दिवाली पर अपनों को गिफ्ट दें और गिफ्ट्स का आदान-प्रदान कर दिवाली मनाएं। आज हमारे यहां दिवाली पर चाइनीज लाइट्स, झालारों नहीं आ रही है। आज हर जगह जहरीली हवा है। कोई भी आज मेट्रो सीटीज में बिना मास्क नहीं धूम सकते हैं। राजधानी दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली समेत एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम) में वायु प्रदूषण का कहर जारी है। दिवाली के आसपास ही पराली का सीजन भी होता है। कुछ समय पहले एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी दैनिक के हवाले से यह खबर आई थी कि दिल्ली में वायु प्रदूषण विश्व स्वास्थ्य संगठन की सीमा से 8 गुना अधिक है। एक रिपोर्ट के अनुसार, वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों और बीमारियों ने साल 2021 में दुनिया भर में 8.1 मिलियन लोगों की जान ले ली, जिनमें से चार में से एक मौत भारत में हुई, यह चौंकाने वाला तथ्य है। पाठकों को यह जानकर आश्वर्य होगा कि चीन (2.3 मिलियन मौतें) और भारत (2.1 मिलियन मौतें) ने 2021 में वायु प्रदूषण से होने वाली दुनिया की 55% मौतें को साझा किया। पीटीआई की एक खबर के अनुसार भारत में सभी स्त्रीों से होने वाले बाहरी वायु प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष 21 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। ह्याद बीएमजेल्स (द ब्रिटिश मेडिकल जर्नल) में

A close-up photograph of numerous small, lit candles in dark, ornate holders, creating a warm and intimate atmosphere.

प्रकाशित अध्ययन के अनुसार बाहरी वायु प्रदूषण भारत में प्रति वर्ष 21 लाख 80 हजार लोगों की जिंदगी छीन लेता है। इस मामले में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। वायु प्रदूषण ही नहीं पटाखों से ध्वनि प्रदूषण भी बहुत होता है। पटाखे का जोरदार धमाका 160 डेसिबल तक होता है, जो मानव स्वास्थ्य के साथ ही धरती पर अच्युत जीव-जंतुओं/प्राणियों के लिए बहुत ही घातक व खतरनाक सांबित होता है। चिकित्सकों के अनुसार पटाखों से कान का पर्दा फटना, सुनाई कम देना, सीटी की आवाज, संपूर्ण बहरापन आदि की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जानकारी देना चाहूंगा कि शिवकाशी भारत के तमिलनाडु राज्य के विरुद्धुनगर जिले का एक शहर है, जो सबसे बड़ा पटाखा कारखाना में से एक है। यह शहर पटाखों और माचिस की फैक्ट्रियों के लिए जाना जाता है, जहाँ देश के 70% पटाखे और माचिस बनाये जाते हैं। जानकारी देना चाहूंगा कि भारत पटाखा उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पर है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के बाद भारत में ही सबसे अधिक पटाखे बनाए जाते हैं। आज भी भारत में पटाखा इंडस्ट्री में बूम देखने को मिलता है। यदि आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले साल ही दिल्ली को छोड़कर पूरे देश में खुदरा पटाखों की बिक्री ने छह हजार करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लिया था, हालांकि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों को लेकर कड़ा रुख अपनाया लेकिन बावजूद इसके भी आज पटाखे की बिक्री धड़ल्ले से होती है तथा दीपावली के अवसर पर विशेषतया रुक्खों पटाखे फोड़े जाते हैं। वास्तव में दीपावली के अवसर पर यदि पटाखों प्रयोग करना ही है तो हमें ग्रीन पटाखों उपयोग करना चाहिए। जानकारी देना चाहूंगा कि ग्रीन पटाखे दिखने और जलने में सामान्य पटाखों की तरह ही होते हैं लेकिन इनसे प्रदूषण कम होता है। इन जलाने पर 40 से 50 फीसदी तक कम हानिकारक गैसें पैदा होती हैं। इन इस्तेमाल से ध्वनि प्रदूषण में भी कमी देखी गई है। ग्रीन पटाखे सामान्य पटाखों तुलना में आकार में छोटे और हल्के हैं, जिससे रोंग मैटीरियल का भी कम होता है। उपयोग होता है। ग्रीन पटाखे धूल अवशेषित करते हैं और इनमें बेरियल नाइट्रेट जैसे खतरनाक तत्व नहीं होते हैं। वास्तव में इन पारंपरिक पटाखों जहरीली धारुओं को कम खतरनाक यौगिकों से बदल दिया जाता है कि भारतीय वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित ग्रीन पटाखों को केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड ने मंजूरी दी है, इसलिए इन पटाखों का उपयोग करके हम अपने परंपराओं का सम्मान करते हुए हृषि पर्यावरण व इस धरती की रक्षा भी सकते हैं। वास्तव में ग्रीन पटाखों उपयोग के साथ ही हमें वोकल्प प्राप्त होता है।

लोकल मतलब स्थानीय दसों उत्पादों के लिए भी आगे आना चाहिए। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को जहां एक और मजबूती मिलेगी, साथ ही साथ इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सुजन के अवसर भी पैदा होंगे। दीपावली के मौके पर हम दीए से लेकर रोशनी और सजावट के लिए विदेशी वस्तुओं विशेषकर चाइनीज लाइटों, झालरों, लड़ियों, इलैक्ट्रोनिक आइटम्स की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन हम अक्सर यह बात भूल जाते हैं कि दीपावली पर उन घरों में भी खुशियों के दीपक जलने चाहिए जो सड़क / फुटपाथ, ठेलों, रेहड़ियों या अन्य जगहों पर अपने हाथों से बनाए/तैयार स्थानीय उत्पाद बेचते हैं। आज हम मिट्टी के दीए कम इलैक्ट्रोनिक लाइटों, झालरों, लड़ियों को ज्यादा जलाते हैं और उनकी चमक-दमक से आकर्षित होते हैं और ऐसा करके हम बिजली की खपत तो अधिक करते ही हैं, हमारे स्थानीय उत्पाद तैयार करने वाले कारिगरों को भी कहीं न कहीं हतोत्साहित ही करते हैं। इलैक्ट्रोनिक लाइटों, झालरों को जलाने की बजाय मिट्टी के दीयों को जलाने से न हमें सिफ सकारात्मक ऊर्जा ही मिलती है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी सहजेने का सादगीपूर्ण, पारंपरिक व सुंदर तरीका है। इसलिए हमें चाइनीज लाइट्स, मोमबत्तियों और रंग-बिरंगी विदेशी झालरों की बजाय दीयों का इस्तेमाल कर स्थानीय कारिगरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका एक फायदा यह भी होगा कि इससे बिजली की भी खपत नियन्त्रित होगी। हमें यह चाहिए कि हम दीपावली पर छोटे, मंज़ले, स्थानीय कामगारों, व्यापारियों, डुकानदारों, हस्त-शिल्पियों, कारीगरों को अधिकाधिक प्रोत्साहित कर वोकल फॉर लोकल अभियान को तवज्ज्ञ देनी चाहिए और हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे समाज को और अधिक मजबूत करना चाहिए। हमारी छोटी छोटी पहलों से ही बहुत कुछ संभव हो सकता है। तो आइए, इस दीपावली हम एक स्वच्छ, हरित और आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्प लें और अपने भारत को सपनों का भारत बनाएं।

बढ़ेगे तो कटेगे कोई नारा नहीं, सचाई है

बाल विवाह पर 'बड़ी अदालत'

का कास्टा

'बाल विवाह मुक्त भारत' से जुड़ संगठन इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक समग्र रणनीति 'पिकेट' पर



आलोचना की, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अलग-अलग तरह से इस संदेश को आगे बढ़ाया है। इसी कड़ी में सरकार्यवाह होसबाले हिन्दू एकता एवं संगठन की आवश्यकता व्यक्त की। सरकार्यवाह होसबाले एक सक्रिय, साहसी, चिन्तनशील, राष्ट्रयोद्धा, समाजसुधारक और बदलाव लाने वाले संघ नेता हैं। वे देशहित में अच्छी रचनात्मक एवं सृजनात्मक बातें उन्होंने दावा किया कि केरल में 20 लड़कियों को लव जिहाद से बचाया गया है ध्यान रहे कि अभी राजधानी दिल्ली वे नांगलोई इलाके में मुस्लिम लड़के सलीम खुद को संजू बताकर हिन्दू लड़की सोनिया को प्यार के जाल में फँसाया। सलीम सोनिया के साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसे गर्भवती कर दिया। सोनिया ने जब शादी बाब बनाया तो सलीम ने दो दोस्तों के साथ उसकी हत्या कर दी और शव को हरियाणा

करते हैं, बदलाव चाहते हैं, राष्ट्र को तोड़ना नहीं जोड़ना चाहते हैं, अच्छी बात यह भी है कि संघ एक जागरूक संगठन है और हर समस्या पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। हर व्यक्ति के दिमाग में एक समस्या है और हर व्यक्ति के दिमाग में एक समाधान है। एक समस्या को सब अपनी समस्या समझे और एक का समाधान सबके काम आए। समाधान के अभाव में बढ़ती हिन्दू समस्या संक्रामक बीमारी का रूप न ले सके, इस दृष्टि से आज का समाधान आज प्रस्तुत करने के लिए आरएसएस निरन्तर जागरूक रहता है। इसीलिये हिन्दू एकता के लिये व्यापक प्रयत्नों की अपेक्षा है। बांग्लादेश में हिन्दू समुदाय के लोगों की परेशानियों को लेकर भारत सरकार ने कदम उठाए हैं। दुनिया में कहीं भी किसी भी हिन्दू को अगर कोई परेशानी होती है तो वह मदद के लिए भारत की तरफ ही देखता है। देश एवं दुनिया में हिन्दुओं से जुड़ी परेशानियों एवं समाधान की दृष्टि से एक सशक्त वातावरण बनाना अपेक्षित है। होसबाले ने ऐसी ही जटिल होती समस्याओं में लव जिहाद का मुद्दा भी उठाया और कहा कि लव जिहाद से समाज में समस्या हो रही है। उन्होंने कहा, ह्यलाइकियों को लव जिहाद के प्रति जागरूक करें। हमारे समाज की अपने ननिहाल के गांव में एक खेत में गांव दिया। निश्चित रूप से बटेंगे तो कटेंगे कोई नारा नहीं बल्कि सदियों की सच्चाई है। जब-जब हिन्दू कमजोर हुआ है, तब तब उस पर अत्याचार बढ़े हैं, उनका सफाया कर दिया गया है तो कश्मीर में हिन्दुओं ने ताकत नहीं दिखाई तो उनका नरसंहार हुआ। लाहौर की 75 प्रतिशत आबादी हिन्दुओं और सिखों की थी, कराची में हिन्दू, सिंधी और हिन्दू पंजाबी जनसंख्या दो तिहाई थे, काबुल में 1950 तक एक तिहाई हिन्दू-सिख थे, रंगून में एक तिहाई आबादी हिन्दुओं की थी, सभी जगहों पर आत्म हिन्दुओं-सिखों का सफाया हो गया। इसीलिये सरकार्यावाह होसबोले की दृष्टि में बटें वे प्रति सचेत करने का मतलब अनेकता एकता का मंत्र है। हम जाति, वर्ग में भी अनेक हों, लेकिन इस आधार पर हम बंद नहीं बल्कि एकजुट रहें। बांग्लादेश के संदर्भ में भारत सरकार ने वहां हिन्दुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। संघ ने उस समय भी कहा था कि हिन्दू समुदाय को वहीं रहना चाहिए और पलायन नहीं करना चाहिए।

संघ की नजरों में धर्मांतरण और हिन्दुओं का विभाजित करने से हिन्दू जनसंख्या ब-

गये हैं। इस मायने में होसबोले का उद्घोधन कोई स्वप्न नहीं, जो कभी पूरा नहीं होता। यह तो हिन्दुओं को सशक्त एवं विकसित बनाने के लिए ताजी हवा की खिड़की है। यह सामाजिक समरसता का भी जीवनमंत्र है। संघ इस संवाद को कायम रखेगा क्योंकि समाज को तोड़ने के लिए बहुत सी कोशिशें हो रही हैं, विपक्षी दल अपने राजनीतिक हितों के लिये हिन्दू समुदाय को तोड़ने एवं विभाजित करने के लिये तरह-तरह के षट्यंत्र कर रहे हैं। एक बार फिर संघ ने राजनीति से परे जाकर देश को जोड़ने, सशक्त बनाने एवं नया भारत निर्मित करने का सन्देश दिया है और इस सन्देश को जिस तरह आकार दिया जाना है, उसका दिशा-निर्देश भी दिया गया है।

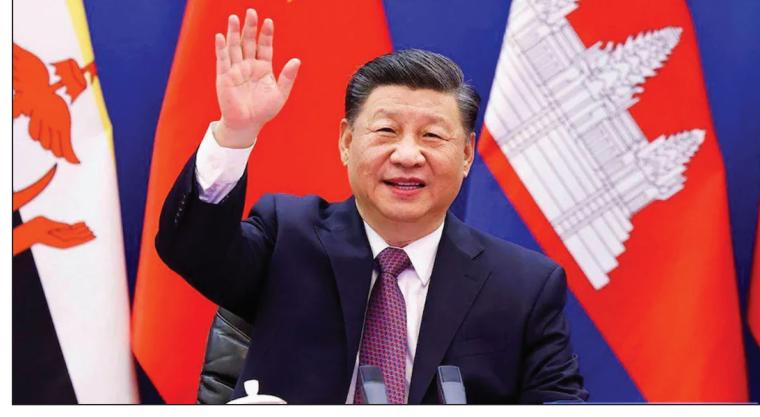
आरएसएस महासचिव ने कहा, महात्मा गांधी

ने भी स्वराज्य का मंत्र दिया था। ह्यस्वलूका
मतलब है ह्यस्वाधीनतालू, राष्ट्रीय स्वत्व। यहाँ
हिन्दुओं को अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता,
उसके अनुभवों के साथ व्यवहार करना है,
आधुनिकता का पालन करना है, आधुनिकता
में भी ह्यस्वलूको नहीं भूलना है। इस ह्यस्वलू
को जीवंतता देकर ही हिन्दू समाज टूटने एवं
बिखरने से बच सकता है। किसी भी समाज
में बिखराव की स्थिति होती है तो उसकी
क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं हो सकता।
उपयोग के लिए क्षमताओं को केन्द्रित करना
जरूरी है। समाज का हर व्यक्ति अपने आप
में एक शक्ति है। इस शक्ति को काम में लेने
से पहले उसे एकात्ममुख करना जरूरी है।
होसबोले के आश्वान का हार्द हिन्दुओं को
सशक्त बनाते हुए राष्ट्र को नयी शक्ति देने का
है। वास्तव में यदि हम भारत को विकसित
राष्ट्र बनाने के अपने सपने को साकार करना
चाहते हैं तो हमें अपनी सोच और अपने तौर-



जुड़ा सालापुर (महाराष्ट्र) का सस्था 'महात्मा फुले समाज सेवा मंडल' के प्रमोद दिंग्जाडे के मुताबिक 'बाल विवाह मुक्त भारत' देश के 400 से अधिक जिलों में बाल विवाह के खात्मे के लिए सक्रिय है। इस गठबंधन से जुड़ी संस्थाओं ने 2023-24 में पूरे देश में 1,20,000 से भी ज्यादा बाल विवाह रुकवाए हैं और 50,000 बाल विवाह मुक्त गांव बनाए हैं। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मोनज मिश्रा की खंडपीठ ने फैसले में कहा है कि 'बाल विवाह प्रतिवेद्य अधिनियम (पीसीएमए) 2006' के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार व प्रशासन को बचाव-रोकथाम-अभियोजन रणनीति के साथ समुदाय आधारित दृष्टिकोण से काम करने की जरूरत है। अदालत ने स्कूलों, धार्मिक संस्थाओं और पंचायती को बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता के प्रसार का अहम जरिया बताते हुए बाल विवाह बहुल इलाकों में राज्यों को 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' की अनुशंसा के अनुरूप 'सेक्स एजुकेशन' को स्कूली पाठ्यक्रम में जाड़ने की अनुशस्त्रा की है। इस शिक्षा में लैंगिक समानता, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों और शारिरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बाल विवाह के प्रभाव के कानूनी पहलुओं के बारे में स्पष्ट जानकारी शामिल होनी चाहिए। याचिका में कहा गया था कि देश में बाल विवाह की स्थिति गंभीर है और उसके खिलाफ बने कानून पर अमल नहीं करके उसकी मूल भावना से खिलाफ़ किया जा रहा है। इस पर फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि कानून तभी सफल हो सकता है जब बहुक्षेत्रीय समन्वय हो। कानून प्रवर्तन अधिकारियों के प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण की आवश्यकता है। हम एक बार फिर समुदाय आधारित दृष्टिकोण की जरूरत पर जोर देते हैं। बाल विवाह एक ऐसा अपराध है जिसने सारे देश को जकड़ रखा है।

चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के ड्रीम प्रॉजेक्ट को बहुत बड़ा झटका



ब्राजीलिया: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ड्रीम प्रॉजेक्ट बेल्ट एंड रोड को बड़ा झटका लगा है। ब्राजील ने ऐलान किया है कि वह बीआरआई में शामिल नहीं होगा। इससे पहले चीन ने योजना बनाई थी कि नवंबर में शी जिनपिंग की ब्राजील यात्रा के दौरान बीआरआई को इलैटेन अमेरिकी देशों में व्यापक तरीके से विस्तार करने पर फोकस किया जाएगा। इससे पहले अमेरिका ने ब्राजील को आगाह किया था कि वह चीन के कर्ज का लान करे जाने वाले बीआरआई के खरों की समीक्षा करें। इस पर चीन आगवलू हो गया था। ब्राजील के अलावा भारत ने भी बीआरआई से किनारा कर रखा है। वहाँ इटानी भी इससे निकल गया है। भारत और ब्राजील दोनों भी ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य हैं और आपस में गढ़े दोस्त हैं। हाल ही में रूस से ब्रिक्स देशों के नेता इकड़ा हुए थे और मुलाकात की थी। साथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के

अमेरिकी चुनाव की स्थिति सर्वे से साफ नहीं हो रही, एक्सपर्ट बोले- 24 साल का सबसे नजदीकी इलेवनशन

वॉशिंगटन: अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए गतिशील होना है। ऐसे में इस समय अमेरिका पूरी तरह चुनावी मोड़ में है। चुनाव से ठीक पहले लातार सर्वे भी जारी हो रहे हैं लेकिन ये तमाम सर्वेक्षण स्पष्ट तौर पर किसी की बढ़त को बताने में नाकाम हो रहे हैं। अभी तक एक सर्वेक्षण में कुछ में कमला हैरिस तो कुछ में जो वाइटन को आगे चिनाया गया है। हालांकि ये बहुत बहुत ज्यादा नहीं रही है। ऐसे में चुनाव विशेषज्ञ इससे साफ है कि मुकाबला बेहद कठीनी बना हुआ है।

पहुंच पा रहे हैं।

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, बीते हफ्ते शुक्रवार को जारी नए नेशनल सर्वे से अमेरिकी राष्ट्रपति पद की बैड में नजदीकी मुकाबला दिखाया गया है। न्यूरॉक टाइम्स और सिपाना कालेज के सर्वे से पता चलता है कि हैरिस और ट्रम्प दोनों 48 प्रतिशत पर हैं। सिपाना सर्वे में भी दोनों 47 फीसदी पर हैं। वाल स्ट्रीट जनल के सर्वे में ट्रम्प को 47 जबकि हैरिस 45 फीसदी पर हैं। इससे साफ है कि मुकाबला बेहद चुनाव पर किसी नीति तक नहीं

मास्को। रूस ने सोमवार को जॉर्जिया में संसदीय चुनावों में हस्तक्षेप के आरोपों को 'निराधार' बताया। वहाँ दूसरी तरफ उत्तरी अटलांटिक संघ संगठन (नाटो) ने कथित 'चुनाव संबंधी उल्लंघनों' की जांच की अपील की। क्रेमिलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, "हम इस तरह के आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं ये कई देशों के लिए मानक बन गया है कि छोटी सी बात पर तुरंत रूस पर हस्तक्षेप का आरोप लगा देते हैं। नहीं, यह सच नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है। आ था और आप पूरी तरह से निराधार हैं।" जॉर्जिया में शनिवार को हुए संघीय चुनावों में 18 पार्टियों ने विस्तार लिया, जिसमें सत्तारूढ़ जॉर्जियाई ड्रीम भी शामिल है,

जिसे 52.99 प्रतिशत वोट मिले। यह पहली बार था कि देश में चुनाव पूरी तरह से अनुपातिक प्रणाली के तहत आयोजित किए गए, जिसमें लगभग 90 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया। जॉर्जियाई राष्ट्रपति सलोमी जाराबिचविली ने चुनाव के परिणामों को खारिज कर दिया और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अवैध सरकार की जगह लोगों के साथ खड़े होकर देश की रक्षा करने अपील की। जाराबिचविली ने एस्ट पर लिखा, "ये चुनाव अवैध हैं! उत्तरी चुनाव प्रक्रिया को 'एक रूसी विशेष अधियान' और 'हाइब्रिड युद्ध' का एक नया रूप बताया है।" जॉर्जिया में शनिवार को हुए संघीय चुनावों में भी चीनी अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद, नाटो ने भी सोमवार की जांच की मांग

जारी की तैयारी कर रहा है क्योंकि सरकार कार्यालय में अपने पहले 100 दिन पूरे कर रही है। ताजा घटनाक्रम को नेपाल के भूरजनीतिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। टिप्पणी के लिए विदेश मंत्रालय से संपर्क करने की कार्यशक्ति की बड़ी तो प्रवक्ता उपलब्ध नहीं थे। हालांकि, विदेश मंत्रालय के एक उच्च स्तरीय स्तर ने कहा कि न तो भारत और न ही चीन ने अब तक प्रधानमंत्री को आधिकारिक यात्रा के लिए निमंत्रण सौंपा है। प्रस्तावित यात्रा जूलाई के मध्य में पदभार ग्रहण करने के बाद ओली

यात्रा की तैयारी कर रहा है क्योंकि नेपाल के साथ बैठक की पहली यात्रा होगी, जो नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में उनका चौथा कार्यकाल है। ओली ने नेपाल के प्रधानमंत्री के संबंधों को बेहतर करने पर लगातार काम कर रहे हैं। उत्तरोने बताया है कि भारत और रूस वित्तीय बाधाओं के बावजूद द्विपक्षीय भूमिका को अधिक व्यवहार बनाने को अवैध क्षवारिया बनाने के लिए कर रहे हैं। दोनों देश आपे अब तक प्रधानमंत्री को आधिकारिक यात्रा के लिए निमंत्रण सौंपा है।

की निकटतम पड़ोसी की पहली यात्रा होगी, जो नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में उनका चौथा कार्यकाल है। ओली ने इन्हें महीने न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) से इतर प्रधानमंत्री

की निकटतम पड़ोसी की पहली यात्रा होगी, जो नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में उनका चौथा कार्यकाल है। ओली ने इन्हें महीने न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) से इतर प्रधानमंत्री

की निकटतम पड़ोसी की पहली यात्रा होगी, जो नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में उनका चौथा कार्यकाल है। ओली ने इन्हें महीने न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) से इतर प्रधानमंत्री

की निकटतम पड़ोसी की पहली यात्रा होगी, जो नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में उनका चौथा कार्यकाल है। ओली ने इन्हें महीने न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) से इतर प्रधानमंत्री

की निकटतम पड़ोसी की पहली यात्रा होगी, जो नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में उनका चौथा कार्यकाल है। ओली ने इन्हें महीने न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) से इतर प्रधानमंत्री

की निकटतम पड़ोसी की पहली यात्रा होगी, जो नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में उनका चौथा कार्यकाल है। ओली ने इन्हें महीने न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) से इतर प्रधानमंत्री

की निकटतम पड़ोसी की पहली यात्रा होगी, जो नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में उनका चौथा कार्यकाल है। ओली ने इन्हें महीने न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) से इतर प्रधानमंत्री

की निकटतम पड़ोसी की पहली यात्रा होगी, जो नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में उनका चौथा कार्यकाल है। ओली ने इन्हें महीने न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) से इतर प्रधानमंत्री

की निकटतम पड़ोसी की पहली यात्रा होगी, जो नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में उनका चौथा कार्यकाल है। ओली ने इन्हें महीने न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) से इतर प्रधानमंत्री

की निकटतम पड़ोसी की पहली यात्रा होगी, जो नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में उनका चौथा कार्यकाल है। ओली ने इन्हें महीने न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) से इतर प्रधानमंत्री

की निकटतम पड़ोसी की पहली यात्रा होगी, जो नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में उनका चौथा कार्यकाल है। ओली ने इन्हें महीने न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) से इतर प्रधानमंत्री

की निकटतम पड़ोसी की पहली यात्रा होगी, जो नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में उनका चौथा कार्यकाल है। ओली ने इन्हें महीने न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) से इतर प्रधानमंत्री

की निकटतम पड़ोसी की पहली यात्रा होगी, जो नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में उनका चौथा कार्यकाल है। ओली ने इन्हें महीने न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) से इतर प्रधानमंत्री

की निकटतम पड़ोसी की पहली यात्रा होगी, जो नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में उनका चौथा कार्यकाल है। ओली ने इन्हें महीने न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) से इतर प्रधानमंत्री

की निकटतम पड़ोसी की पहली यात्रा होगी, जो नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में उनका चौथा कार्यकाल है। ओली ने इन्हें महीने न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) से इतर प्रधानमंत्री

की निकटतम पड़ोसी की पहली यात्रा होगी, जो नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में उनका चौथा कार्यकाल है। ओली ने इन्हें महीने न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) से इतर प्रधानमंत्री

की निकटतम पड़ोसी की पहली यात्रा होगी, जो नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में उनका चौथा कार्यकाल है। ओली ने इन्हें महीने न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) से इतर प्रधानमंत्री

की निकटतम पड़ोसी की पहली यात्रा होगी, जो नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में उनका चौथा कार्यकाल है। ओली ने इन्हें महीने न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) से इतर प्रधानमंत्री